

(ग) पयटन सर्वेक्षण दल की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार निम्न-लिखित प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है:—(क) चित्तौड़गढ़ में टॉयलेट मुविधायों सहित एक कैंटीन की व्यवस्था; (ख) फोर्ट के लिए तथा उसके अंतर्गत संदर्शित कोच यात्राओं का परिचालन; तथा (ग) दिल्ली-जयपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर के बीच तीव्रगामी गाड़ियों के परिचालन की संभावना का अनुसंधान।

उत्तर प्रदेश में कटाई और कपड़ा मिलों का बन्द होना

5465. श्री राम प्रसाद बेशमुख : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बन्द होने वाली कटाई एवं कपड़ा मिलों की कुल संख्या तथा नाम क्या हैं और उनमें तक़ुओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन मिलों के बन्द होने के परिणाम-स्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार हुए; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन श्रमिकों को नौकरी देने का है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) से (ग). जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स लि०, कानपुर नामक एक सूती वस्त्र मिल बंद पड़ी है, जिसकी वजह से 25,780 तक़ुएं और 189 करघे बेकार पड़े हैं तथा लगभग 2,276 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मिल को पुनः चलाने की दिशा में प्रयास कर रही है ताकि श्रमिक काम पर वापस लौट सकें।

Tripartite Meeting on impending Strikes in Jute Mills

5466. SHRIMATI V. JAYALAKSHMI: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether tripartite meeting on the impending strikes in the Jute industry was held at Calcutta; and

(b) if so, what decisions were taken thereat to prevent the closure of the jute mills?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) and (b). In the context of the situation arising out of shortage of raw jute Commerce Minister held a meeting on 3rd July, 1977, in Calcutta with the representatives of jute industry, labour and Government of West Bengal. The following main decisions were taken in this meeting:—

(i) Block closure of jute mills would not be allowed.

(ii) A Committee under the chairmanship of the Jute Commissioner would be constituted with immediate effect to study the current raw jute supply situation and to recommend measures therefor. The members of the Committee would include representatives from the industry, labour and the Government of West Bengal.

(iii) The Jute Commissioner was asked to immediately issue a notice under the Jute (Licensing and Control) Order requiring all stockists of raw jute to disclose their stocks before him within 48 hours. Any violation of this directive or furnishing false information was to be dealt with severely under the Essential Commodities Act, 1955. The State Government was requested to extend all necessary help.

(iv) The State Government also agreed not to entertain any application from individual mills for exemption from the Energy Control